

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अवसर एवं चुनौतियाँ

डॉ. सुनीता जैन

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

स्व. दिलीप भट्टे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सारांश –

इस शोध पत्र में नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सर्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के सहयोग से अत्याधुनिक क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा और शोध किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की रीढ़ होते हैं। यह अनायास नहीं है कि दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों में उच्च शिक्षा को लेकर सरकारी और नियामक संस्थाएं अत्यंत सजग हैं। दुर्भाग्य से भारत में उच्च शिक्षा की नियामक एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न सरकारों का रवैया उच्च शिक्षा को लेकर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। वास्तव में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है, लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की चतुर्दिक समस्याओं में से उच्च शिक्षा की समस्या की तह में जाना ज्यादा जरूरी है। शिक्षा किसी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है।

मुख्य शब्द – राष्ट्रीय, शिक्षा, नीति, अवसर, चुनौतिया, उच्च शिक्षा, आदि ।